अपनी बात

तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता दे चीन

तिब्बत समस्या को सुलझाकर ही विष्व में, विषेषकर एषिया में शांति लाई जा सकती है। तिब्बत की निर्वासित सरकार चीन के संविधान में वर्णित स्वायत्तता दिए जाने की मांग कर रही है। इसी तरह के प्रावधान चीन के क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता कानून में भी हैं। वास्तविक स्वायत्तता मिलने के बाद तिब्बत सरकार भाषा, संस्कृति, धर्म, षिक्षा, पर्यावरण–संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक विकास एवं वाणिज्य–व्यापार, जन स्वास्थ्य, जन सुरक्षा तथा जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़े विषयों पर स्वयं निर्णय लेने लगेगी। वे निर्णय उसी द्वारा क्रियान्वित भी किए जायेंगे। साथ ही इन विषयों के संबंध में वह पड़ोसी देषों से भी संपर्क कायम कर सकेगी। इसी वास्तविक स्वायत्तता को ''मध्यम मार्ग'' कहा जाता है। चीन से आजाद हुए बिना तिब्बत में स्वषासन की स्थापना। यह तिब्बत के हित में होने के साथ ही चीन के भी हित में होगा। ऐसी व्यवस्था चीन के संविधान और क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता कानून की गरिमा को बढ़ाने में काफी मददगार होगी।

अफसोस की बात है कि चीन सरकार स्वायत्तता संबंधी अपने ही संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करती आ रही है। तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने की जगह चीन सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है कि तिब्बत को स्वायत्तता दे दी गई है। वास्तविकता यह है कि अपना अवैध नियंत्रण कायम करने के साथ ही चीन सरकार ने तिब्बत का अंगभंग कर दिया। उसकी भौगोलिक सीमाओं में मनमाने फेरबदल कर दिए। इसलिए चीन द्वारा प्रचारित 'स्वायत्तता' तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार द्वारा मांगी जा रही 'वास्तविक स्वायत्तता' के अंतर को समझना होगा। तिब्बत को तथाकथित स्वायत्तता नहीं, वास्तविक स्वायत्तता चाहिए।

चीन सरकार द्वारा तिब्बत में जारी क्रूरतापूर्ण अमानवीय दमनात्मक नीति लगातार अधिकाधिक आक्रामक होती जा रही है। चीन सरकार को अच्छी तरह पता है कि उसने तिब्बत पर नाजायज ढंग से नियंत्रण कर लिए हैं और उसे देर–सबेर तिब्बत से खदेड़ा ही जाएगा। इसी कारण वह तिब्बत को मटियामेट कर रही है। क्या चीन सरकार चीन के अभिन्न अंग को भी मटियामेट करती? वहाँ के प्राकृतिक संसाधन नष्ट किए जा रहे हैं। वहाँ पर्यावरण संकट में है, क्योंकि चीन की गलत नीतियों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सभी प्रकार के मानवाधिकार खतरे में हैं। तिब्बती अपने ही देष में अल्पसंख्यक होने लगे हैं, क्योंकि वहाँ चीनी मूल के अधिकाधिक लोगों को साजिषपूर्वक बसाया जा रहा है। तिब्बती अपने ही देष में नौकर बना दिए गए हैं, क्योंकि नीति–निर्णायक पदों पर, कार्यक्रमों को लागू करने वाले पदों पर तथा प्रमुख सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक–शैक्षणिक–प्रषासनिक पदों पर चीनी मूल के लोगों का बर्चस्व कायम हो गया है।

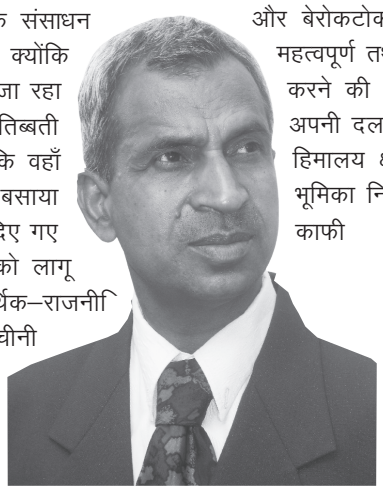

तिब्बती अपने ही देष में सब प्रकार की कानूनी स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं। धर्मप्रधान तिब्बत में प्रमुख धर्माधिकारियों के पदों पर भी चीन की सरकार ही अपने समर्थकों को षड्यंत्रपूर्वक बैठा रही है। ज्ञातव्य है कि चीन की साम्यवादी सरकार धर्म को अफीम कहती है तथा नास्तिकता को बढ़ावा देती है, लेकिन तिब्बत के धार्मिक मामलों में निर्णायक रूप से दखल दे रही है। ह्यूमन राइट्स वाच की 2014 की वार्षिक रिपोर्ट में तिब्बत की बदहाली का दर्दनाक ब्यौरा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विष्वस्तर पर तिब्बत समस्या के समाधान के लिए चल रहे आंदोलन में ज्यादा गंभीरता आई है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्ट के सम्मान की उम्मीद चीन सरकार से करना मुष्किल है। वह तो अपने संविधान का ही उल्लंघन कर रही है। जनवरी 2014 में तिब्बत की गंभीर स्थिति को बताने के लिए तथा समाधान के रूप में वास्तविक स्वायत्तता संबंधी ''मध्यम मार्ग'' को स्पष्ट करने के लिए तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री (सिक्योंग) डॉ. लोबजंग संग्ये ने महत्वपूर्ण भारतीय राजनेताओं से मुलाकात की है। परमपावन दलाई लामा जी भी कर्णाटक, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेष आदि राज्यों में संपन्न अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में मध्यम मार्ग का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि तिब्बत की धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा विष्वषांति, अहिंसा, करूणा एवं मैत्री का वातावरण मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। चूँकि चीन सरकार इस विरासत को बर्बाद करने में लगी है, इसलिए आवष्यक है कि मानवता के हित में तिब्बत को चीन के संविधान में वर्णित ''वास्तविक स्वायत्तता'' दे दी जाए। उनके मतानुसार इससे चीन की एकता–अखंडता भी कायम रहेगी तथा पूरे एषिया में शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण होगा।

भारतीय समाज, विषेषकर राजनेताओं को तिब्बत समस्या के समाधान हेतु चीन सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहिये। यह भारत के राष्ट्रीय हित में होगा। तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता मिल जाए तब भी चीन सरकार तिब्बत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगी। तिब्बत में शांति होने से भारत की एकता–अखंडता ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय कैलाष–मानसरोवर की पवित्र धार्मिक यात्रा निःषुल्क और बेरोकटोक कर सकेंगे। सभी उपयुक्त संचार माध्यमों में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को व्यापक पैमाने पर प्रकाषित–प्रचारित–प्रसारित करने की जरूरत है। इस कार्य में सभी राजनीतिक दलों को अपनी दलगत बंदिषों को ठंडे बस्ते में डालते हुए भारत, तिब्बत, हिमालय क्षेत्र तथा एषिया महादेष के व्यापक हित में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ◆

प्रो0 ष्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खेतड़ी (राज.)
ek-&9829806065] 8764060406
E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

तिब्बत में सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे ताकना जिग्मे सांगपो की जीवनी का लोकार्पण

मैक्ल्योडगंज में 24 जनवरी को एक पुस्तक लोकार्पण समारोह में सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे, ताकना जिग्मे सांगपो (बीच में) और तिब्बती सांसद जामयांग सोएपा (बाएं)। फोटोः फायूल/कुनसांग गशोन

(तिब्बत डॉट नेट, 24 जनवरी)

सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे ने 24 जनवरी को मैक्ल्योडगंज के गु–छु–सुम कॉन्फ्रेंस हॉल में तिब्बत के सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे ताकना जिग्मे सांगपो की जीवनी "मेत्से न्योंगत्सर" का लोकार्पण किया।

इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में सुरक्षा विभाग के कालोन धोंगछुंग गोधुप, तिब्बती संसद के सदस्य श्री जामयांग सोपा, तिब्बत के गु–छु–सुम आंदोलन के अध्यक्ष श्री पसांग सेरिंग भी उपस्थित थे। गु–छु–सुम तिब्बत के पूर्व राजनीतिक कैदियों का एक एनजीओ है।

इस समारोह को संबोधित करते हुए सिक्योंग डॉ. लोबसांग सेंगे ने कहा, "मैं ताकना जिग्मे सांगपो की जीवनी का लोकार्पण कर सम्मानित अनुभव कर रहा हूं। दिल्ली में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जब मैं एक एक्टिविस्ट था, तब से मैंने ताकना जिग्मे सांगपो को ड्रापची जेल में कैद रखने के बारे में सुन रखा था और उनके वीरतापूर्ण कार्यों से मैंने प्रेरणा ली है।"

सिक्योंग ने कहा, "यहां तक कि जेल के अंदर रहते हुए भी ताकना जिग्मे सांगपो ने विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां चलाई थीं। एक ऐसा ही बड़ा विरोध प्रदर्शन 1992 में ड्रापची जेल में स्विट्जरलैंड के मानवाधिकार अधिकारियों के दौरे के समय हुआ था, जब ताकना ने तिब्बत की स्वाधीनता के नारे लगाए थे, हालांकि इसके बाद चीनी अधिकारियों ने उन्हें चुप करा दिया।"

डॉ. लोबसांग सांगे ने कहा, "ताकना जिग्जे सांगपो, तिब्बत के सबसे लंबे समय के राजनीतिक कैदी, तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों के स्थायी उदाहरण हैं। उनके माध्यम से, मैं सभी पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदियों और चीनी कब्जे वाले तिब्बत में उत्पीड़न का शिकार हो रहे सभी लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं।"

ताकना जिग्मे सांगपो ने अपने संबोधन में इस जीवनी को लोकार्पित करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह है तिब्बती जनक्रांति दिवस की 28वीं वर्षगांठ पर परमपावन दलाई लामा का भाषण।"

सांगपो ने याद करते हुए कहा, "उस भाषण में परमपावन ने तिब्बतियों की पुरानी पीढ़ी से आह्वान किया था कि वह अपने अनुभवों को लेखबद्ध करें। उन्होंने कहा था कि यदि आप बलिदानों और उत्पीड़न का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो इस बात की आशंका रहती है कि आपके बलिदान धीरे– धीरे लोग भूलने लगेंगे।"

उन्होंने बताया कि कालोन त्रिसूर प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे और कालोन दोंगछुंग गोधुप ने इस जीवनी को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। ताकना जिग्मे सांगपो को स्वास्थ्य कारणों से 31 मई, 2002 को रिहा कर दिया गया था और तब तक वह जेल में तीन दशक से भी ज्यादा समय तक बिता चुके थे। पहली बार उन्हें 1960 में तब गिरफ्तार किया गया था, जब वह ल्हासा के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। उन पर "बच्चों के दिमाग को प्रतिक्रियावादी सोच के साथ दूषित करने" का आरोप लगाया गया था। वर्ष 1964 में उन्हें दूसरी बार कारावास की सजा सुनाई गई और चीनियों द्वारा तिब्बतियों के दमन के बारे में टिप्पणी करने के आरोप में उन्हें तीन साल जेल में रखा गया। उन पर यह भी आरोप था कि थामजिंग (संघर्ष) सत्रों के दौरान उन्होंने स्वर्गीय पंचेन लामा की आलोचना करने से इनकार किया था। ताकना जिग्मे सांगपो की जीवनी ल्हाछाब जिनपा और पूज्यनीय थुबटेन यारफेल ने लिखी है। ◆

भिक्षुओं की चीन सरकार द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ 500 तिब्बतियों ने किया प्रदर्षन

एक अति सम्मानित तिब्बती भिक्षु की रिहाई की मांग को लेकर काउंटी जेल के बाहर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों आम जन जमा हो गए। फोटोः एपी

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 18 जनवरी, 2014)

करीब 500 तिब्बतियों ने, जिनमें 60 भिक्षु भी थे, गत 15 जनवरी को क्विंघई प्रांत के युलशुल प्रशासनिक क्षेत्र स्थित नांगछेन काउंटी में विरोध प्रदर्शन किया है। ये तिब्बती एक सम्मानित धार्मिक हस्ती और कुछ अन्य भिक्षुओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। रेडियो फ्री एशिया की 16 जनवरी की खबर के अनुसार विरोध प्रदर्शनकारी कुछ घंटों बाद तितर–बितर हो गए, लेकिन उन्होंने यह संकल्प लिया कि यदि प्रशासन अपने वादों को पूरा नहीं करता है और गिरफ्तार भिक्षुओं से कुछ भिक्षुओं को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो वे फिर से इसी तरह का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे।

खबर में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि नांगछेन जन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख ने इस बात पर हामी भरी है कि वह 60 विरोध प्रदर्शन करने वाले जापा भिक्षुओं को दो समूहों में गिरफ्तार भिक्षुओं से मिलने की इजाजत देंगे, यदि वे अपने विरोध प्रदर्शन को वापस ले लें। गिरफ्तार सबसे प्रमुख व्यक्ति मठ के अध्यक्ष कर्मा सेवांग (कार्तसे) को तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र के चामदो में रखा गया है। उन्हें 6 दिसंबर को चामदो पुलिस के एक दल ने गिरफ्तार किया था, जब वह नांगछेन काउंटी के अपने जापा मठ के लिए सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू में खरीदारी कर रहे थे। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह चामदो के कर्मा कस्बे में हुई चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसके बाद दिसंबर के अंत में पुलिस ने नांगछेन में जापा मठ के 16 अन्य भिक्षुओं को काफी विरोध प्रदर्शन के बीच गिरफ्तार कर लिया, हालांकि अगले हफ्ते इनमें से 9 को रिहा कर दिया गया। रिहा हुए भिक्षुओं ने बताया कि चीनी प्रशासन उनसे यह जानना चाह रहा था कि खेनपो कार्तसे बाहरी सूत्रों से किस तरह से संपर्क करते हैं। इसके बाद 15 जनवरी को विरोध प्रदर्शनकारियों ने अन्य भिक्षुओं को भी रिहा करने की मांग की। खेनपो कार्तसे युलशुल की काफी सम्मा. नित धार्मिक हस्ती हैं जो अप्रैल 2010 में आये भूकंप से विनाश के दौरान राहत प्रयासों के लिए चर्चित रहे हैं। वे तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को बढ़ावा देने और उसे बचाये रखने के लिए भी जाने जाते हैं। ◆

तिब्बती भिक्षुओं को हिरासत में लेते हुए चीनी सुरक्षा बल के जवान। फोटोः एक चीनी सैन्य मंच स्रोत से

चीन नियंत्रित तिब्बत दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार दषाओं वाले इलाकों में

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 25 जनवरी, 2014)

चीनी शासन वाला तिब्बत दुनिया में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सबसे खराब दशाओं वाले 12 जगहों में से एक है। अमेरिका मानवाधिकार संगठन फ्रीडम हाउस की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। तिब्बत को राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के 55 देशों और इलाकों में से सबसे खराब संभव रेटिंग 7 में से 7 हासिल हुई है और उसे "आज़ाद नहीं" का दर्जा दिया गया है।

"चीनी नियंत्रित तिब्बत" के साथ इस सूची में सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गुएना, एरिट्रिया, सूडान और पश्चिमी सहारा शामिल हैं।

वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और नागरिक आज़ादी की सालाना "फ्रीडम इन द वर्ल्ड" रिपोर्ट 2014 में परेशान करने वाले नये चलन और आधुनिक एकाधिकारवाद के उभार का विवरण दिया गया है।

इसमें बताया गया है कि अब जो एकाधिवारवादी शासक हैं उनका पूरा ध्यान विपक्ष को खत्म किये बिना उनको कमजोर कर देने और कानून के शासन की धज्जियां उड़ाने पर है और यह सब व्यवस्था, वैधानिकता और समृद्धि के चोले में हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन पर निगरानी कर असंतुष्टों और लोकतंत्र के समर्थकों पर निगरानी रखना दमन का नया औजार बन गया है। फ्रीडम हाउस की एशिया रिसर्च एनालिस्ट सारा कुक ने चीन के बारे में कहा, "इस साल चीन के अंक में कोई बदलाव नहीं आया है। राजनीतिक अधिकारों के मसले पर इसे 7 अंक (1 से 7 के पैमाने पर) और नागरिक अधिकारों के मसले पर 6 अंक हासिल हुए हैं और कुल मिलाकर यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से है। चीन में अब भी दुनिया में आज़ादी न हासिल कर सकने वाले लोगों की आधी जनसंख्या है। ◆

तिब्बत अब भी कर रहा है 2008 जैसे बर्बर दमन का सामना

तिब्बत की राजधानी ल्हासा में सड़कों पर गश्ती करते चीनी पुलिस के जवान। फोटोः एपी

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 24 जनवरी)

गत 21 जनवरी को न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच द्वारा जारी वर्ष 2013 के लिए सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में तिब्बत में चीन का रिकॉर्ड बेहद खराब है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग अब भी कई अत्यंत दमनकारी कदम जारी रखे हुए है जो कि 2008 में शुरू हुए व्यापक तिब्बती विरोध प्रदर्शन के बाद उठाए गए थे। इनमें "अर्द्धसैनिक बलों से भरे सशस्त्र पुलिस बल के रूप में भारी सुरक्षा बंदोबस्त, तिब्बती पठार में तिब्बतियों की आवाजाही पर सख्त अंकुश, मठों पर नियंत्रण बढ़ाने और सरकारी प्रयोजित टूर के अलावा अन्य किसी भी रूप में विदेशी पत्रकारों के तिब्बत स्वायत्तशासी इलाके में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है।"

इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चीन व्यवस्थित रूप से तिब्बतियों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को छीन रहा है और यह सब कथित रूप से अलगाववादी गतिविधियों से निपटने के नाम पर हो रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "मनमानी गिरफ्तारी और कैद में डाल देना आम बात है और जेल में प्रताड़ना तथा दुर्व्यवहार तो वहां का चलन ही बन गया है। राजनीतिक न्यायपालिक की वजह से निष्पक्ष मुकदमा नामुमकिन है जिसका दिखावे के लिए लक्ष्य अलगाववाद को दबाना है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने तिब्बत, शीक्यांग और आंतरिक मंगोलिया के नस्लीय रूप से अल्पसंख्यकों वाले इलाकों में भारी दमनकारी नीतियां अपनाई हैं और वहां बड़े पैमाने पर लोगों का जबरन विस्थापन और नए मकानों में रहने को मजबूर किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत स्वायत्तसाशी क्षेत्र (टीएआर) में बीस लाख से ज्यादा तिब्बती किसानों और चरवाहों को जबरन 'नए मकानों' में बसा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी तिब्बती पठार के लाखों घुमंतू चरवाहों को "नए समाजवादी गांवों" में बसा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन सरकार ने टीएआर में 20,000 नए अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। हर गांव में तैनात ये लोग विद्रोहियों की राजनीतिक विचारों पर सख्त निगरानी रखने के लिए लगाए गए हैं। रिपोर्ट में पिछले साल 6 जुलाई को सिचुआन प्रांत के नित्सो कस्बे में निहत्थे तिब्बतियों पर हुई पुलिस गोलीबारी की भी सख्त आलोचना की गई है जो कि अपने आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा के जन्म दिन को मनाने के लिए जुटे थे। ◆

विष्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देः दलाई लामा

(रायपुर, 14 जनवरी, टाइम्स न्यूज नेटवर्क)

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा कि लोग भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें फूल चढ़ाते हैं और ऐसा सिर्फ एक रस्म के तौर पर करते हैं, बिना इसका अर्थ जाने। उन्होंने यहां पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में नागार्जुन के दर्शन पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा, "जापान और चीन जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में छात्र पूजा करने वाले भिक्षुओं से भी संस्कृति की बेहतर जानकारी रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।"

नागार्जुन के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए दलाई लामा ने कहा, "प्यार, करुणा एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिसे एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य में विकसित होना जरूरी है। खुशी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत आंतरिक मजबूती और आत्मविश्वास है। दिमाग में जानकारी और दिल में अनुभव एक साथ आना चाहिए। अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि कुछ न किया जाए। इसका मतलब यह है कि कोई जबर्दस्ती नहीं, कोई हिंसा नहीं। मुझे अपने जीवन में काफी चीजों का सामना करना पड़ा है। 24 साल की उम्र में मैंने अपना देश खो दिया, 60 वर्ष की आयु में मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सबके बावजूद आपको अच्छा व्यक्ति होना चाहिए।"

इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, "नागार्जुन को आयुर्वेद और चिकित्सीय बुद्ध के रूप में याद किया जाता है। हम भाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ में नागार्जुन के अवशेष हैं।" इस सेमिनार को तिब्बती अध्ययन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति गवांग सामतेन और रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के कुलपति एस.के. पांडेय ने भी संबोधित किया। इस बीच, 14 जनवरी को दलाई लामा ने नागार्जुन गुफाओं का दौर कर इन प्राचीन गुफाओं में ध्यान किया। ◆

तिब्बत के हालात और खराब हुए

उत्तरी प्रशासनिक क्षेत्र कार्डजे के सरथा काउंटी में सड़कों पर गश्त करते चीनी सैनिक।

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 21 जनवरी, 2014)

आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2013 में चीनी शासन वाले तिब्बत में हालात और बदतर हुए हैं। धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने गत 20 जनवरी को यह जानकारी दी है। वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट और तिब्बत में मजदूरी प्रथा के द्वारा पुनर्शिक्षा पर एक विशेष रिपोर्ट जारी करते हुए इस केंद्र ने बताया कि पिछले साल 119 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया है या सजा सुनाई गई है, जिसमें दो लोगों को मौत की सजा और एक व्यक्ति को विलंबित मौत की सजा सुनाई गई है। केंद्र ने कहा कि पिछले साल के दौरान विरोध प्रदर्शन के तहत 27 तिब्बतियों आत्मदाह किया है, जिससे फरवरी 2009 के बाद आत्मदाह करने वालों की संख्या 125 तक पहुंच गई है। चीन की राजनीतिक दमन की नीति के तहत करीब 60,000 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस तरह हर 50 तिब्बती पर पर एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

इसी तरह, तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के नागछू प्रशासनिक क्षेत्र स्थित ड्रिरू काउंटी में सितंबर, 2013 में 18,000 चीनी कम्युनिस्ट कैडर को भेजा गया है। इस इलाके में चीनी लाल झंडा फहराने के आदेश का लगातार बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जिसके बाद बहुत से लोगों की गिरफ्तारी, हत्याएं, मठों को बंद करना, जबरन राजनीतिक शिक्षा और अन्य कई तरह की दमनकारी घटनाएं हो रही हैं। तिब्बती जनता पर चीन द्वारा लगातार प्रतिबंधों और नियंत्रण को सख्त करने तथा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर देने की वजह से केवल 157 तिब्बती ही वहां से जान बचाकर किसी तरह अपने कब्जे वाले मातृभूमि से भागकर बाहर आये हैं।

इस रिपोर्ट में तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति के सभी पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, लेकिन इसकी विशेष थीम है चीन द्वारा जबरन नोमैड के पुनर्वास और विस्थापन की नीति। रिपोर्ट के अनुसार व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि वर्ष 2013 के अंत तक क्विंघई प्रांत के 90 फीसदी तिब्बती घुमंतुओं को जबरन शहरी बस्तियों में बसा दिया गया है। मानवाधिकार केंद्र ने कहा, इस रिपोर्ट में कनाडा के ओंटारियो स्थित ग्यूएल्फ यूनिवर्सिटी के मानवाधिकार विद्यार्थियों का सहयोग लिया गया है। ◆

चीन में अमेरिका के प्रस्तावित राजदूत ने मानवाधिकार के लिए काम करने की बात कही

अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर मैक्स बाउकस

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 30 जनवरी, 2014)

मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा बुनियादी लक्ष्य है और चीन दलाई लामा के साथ सार्थक वार्ता फिर से शुरू करे, यह हमारे एजेंडे में है। अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर मैक्स बाउकस ने 28 जनवरी को यह बात कही, जब उनके चीन में अमेरिकी राजदूत बनने की बात पुष्ट हो गई। रेडियो फ्री एशिया की 28 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार मोनटाना के 72 वर्षीय डेमोक्रेट सीनेटर बाउकस ने कहा, "मानवाधिकारों की रक्षा मूलभूत लक्ष्य होगा।" उन्होंने यह वादा किया कि वह चीनी नेताओं से आग्रह करेंगे कि वह, "नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों को आज़ादी सुनिश्चित करे।" उन्होंने कहा, "मैं चीनी प्रशासन से आग्रह करूंगा वह स्वतंत्र सिविल सोसाइटी को सामाजिक चुनौतियों से निपटने में भूमिका निभाने की इजाजत दे, तनाव दूर करने के कदम उठाए, तिब्बत एवं सीक्यांग में दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा दे और दलाई लामा के साथ फिर से सार्थक वार्ता की शुरुआत करे।"

उन्होंने कहा कि वह चीन को इस बात के लिए राजी करेंगे कि वह खुलकर बहस और सूचनाओं के प्रवाह को बढ़ावा दे क्योंकि यह उसके अपने हित में है। बाउकस वर्ष 1972 से ही सीनेटर रहे हैं और फिलहाल अमेरिका की ता. कतवर सीनेट वित्त समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने दिसंबर में गैरी लॉक के इस्तीफा देने के बाद उन्हें चीन में राजूदत बनने के लिए नामांकित किया था। ◆

चीन ने तिब्बती घुमंतुओं को जबरन कहीं और बसाने का प्रोजेक्ट पूरा किया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 26 जनवरी, 2014)

चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) के 23 लाख नोमैड (घूमंतु लोगों) को जबरन स्थायी मकानों वाले शहरी बस्तियों में बसाने का एक विवादास्पद प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। यह प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया गया था। वायस ऑफ अमेरिका ने तिब्बत के सरकारी टीवी वेबसाइट के हवाले से यह खबर दी है।

वेबसाइट में जहां इस सरकारी प्रोजेक्ट के पूरे होने की जानकारी दी गई है, वहीं यह भी बताया गया है कि क्विंघई प्रांत के पंचवर्षीय योजना के तहत भी 90 फीसदी नोमैड को इस साल के अंत तक नए जगहों पर बसा दिया जाएगा। खबर के अनुसार चीन घुमंतू चरवाहों को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वह पशुध ान सहकारी बस्तियों में रहें जो असल में बहुत संकरी शहरी बस्तियां हैं। ये सहकारी बस्तियां सरकार द्वारा संचालित होती हैं और इसमें तिब्बती अपने पशुओं की चराई नहीं करा सकते।

खबर के अनुसार चीन के पर्यावरण आंदोलनकारी और पत्रकार वांग योंगछेन ने कहा है कि उनका संगठन ग्रीन अर्थ वालंटियर्स पहले से ही बीजिंग में वरिष्ठ अधिकारियों से तिब्बती नौमैड की जबरन विस्थापन पर चिंता जताता रहा है और उसका मानना है कि तिब्बती घुमंतू लोगों की जो जीवन शैली है उससे पर्यावरण की रक्षा होती है। ग्रीन अर्थ वालंटियर्स तिब्बत पठार में पर्यावरणीय चुनौतियों पर रिसर्च कर रहा है और यह पाया गया है कि घूमंतू संस्कृति से उस इलाके में पर्यावरण टिकाऊ बना हुआ है, न कि उसका कोई विनाश हुआ है जैसा कि चीन सरकार दावा कर रही है। ◆

तिब्बतियों का समर्थन करना लोकतांत्रिक नेपाल का कर्तव्य है

(सिद्धार्थ गौतम, द कमांडर पोस्ट डेली, 2 जुलाई, 2013)

किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता का सम्मान करना और अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की ऐसे देश की विरोधी गतिविधि न होने देना किसी भी लोकतांत्रिक देश की बुनियादी विशेषता होती है। नेपाल अपने पड़ोसी देशों भारत और चीन के बारे में यही नीति अपनाता रहा है। पड़ोसियों के प्रति ऐसी नीति अपनाना पूरी तरह से सामान्य बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल को किसी भी देश के नागरिकों द्वारा लोकतंत्र, स्वाधीनता या स्वायत्तता के लिए उठाई जाने वाली मांग का दमन किया जाए, चाहे वह मांग देश के भीतर की जा रही हो या बाहर। लोगों की ऐसी मांग से न तो राष्ट्रीय एकता में कोई अड़चन आती है और न ही इसे राज्य के विरुद्ध अपराध माना जा सकता। केवल चीन जैसे तानाशाह देश ही लोकतंत्र और स्वाधीनता के लिए उठाई जाने वाली आवाज को देश को तोड़ने या देश विरोधी गतिविधि का दर्जा दे सकते हैं, नेपाल जैसा लोकतांत्रिक देश नहीं।

इसलिए नेपाल को चीन के भीतर या बाहर या कहीं भी तिब्बती जनता द्वारा उठाई जाने वाली लोकतंत्र, स्वाधीनता और स्वायत्तता की आवाज को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। यदि नेपाल में ऐसी आवाज उठाई जाती है तो इसका विरोध या दमन नहीं होना चाहिए। नेपाल में भी कई बार लोकतंत्र को हड़प लिया गया और यह जन आंदोलनों के द्वारा हासिल हुआ है। ऐसे समय में नेपाल दुनिया भर से मदद की उम्मीद करता था। जब घर में लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है तो दूसरों से मदद मांगना और इसी मसले पर दूसरों का समर्थन न करना पाखंड तो है ही, अनैतिक भी है। नेपाल की जनता ऐसी पाखंडी और अनैतिक नहीं है। इसलिए नेपाल की जनता का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी दोनों है कि लोकतंत्र और स्वाधीनता हासिल करने के तिब्बतियों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करें। इसी तरह हमारी सरकार नेपाली जनता के ऐसे कर्तव्य के खिलाफ नहीं जा सकती। यदि वह जनता के विरुद्ध जाती है तो सही अर्थों में इसे जनता की सरकार नहीं बल्कि एक दमनकारी सरकार कहा जाएगा। नेपाली जनता संस्कृति, धर्म और सभी जातियों एवं समुदायों के संरक्षण एवं विकास के लिए संघवाद की मांग कर रही है। नेपाल इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह जब तिब्बती जनता अपने देश के संविधान के मुताबिक स्वायत्तता की मांग कर रही है तो नेपाल इसके खिलाफ कैसे हो सकता है, जबकि यह साफ दिख रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार संविधान की भावना

और शब्दावली के खिलाफ जा रही है। नेपाल सरकार यदि सोचती है कि तिब्बती जनता को अपने देश के संविधान में दिये अधिकारों के लिए मांग उठाने का अधिकार नहीं है तो वह नेपाली जनता को उसके संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करने देगी। इसलिए नेपाल की जनता और अधिकारियों का करमापा के जन्म दिन या इसी तरह के अन्य समारोह में जुटने पर आपत्ति जताने की कोई वजह नहीं हो सकती।

सरकार का यह तर्क बिल्कुल वाजिब नहीं है कि दलाई लामा का जन्म दिन नहीं मनाया जाना चाहिए, जबकि उसने माओ के जन्म दिन मनाने की इजाजत दी है। लोग दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध हस्ती का जन्म दिन मना सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं। लोगों के इस बुनियादी अधिकार पर रोक लगाना चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन नेपाल जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए तो यह रोक निश्चित रूप से असामान्य है। ऐसे समारोहों में हिस्सेदारी करने वाले लोगों पर आरोप लगाना तत्काल बंद करना चाहिए। चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहां न तो लोकतंत्र है और नही किसी तरह का मानवाधिकार। वहां एक पार्टी की तानाशाही चलती है। चीन की सरकार लोकतंत्र की मांग करने वालों को टैंक से कुचलने में शर्म या झिझक महसूस नहीं करती। दुनिया भर के लोगों द्वारा आलोचना या घृणा का चीन पर कोई असर नहीं होता। तानाशाह चीन द्वारा तिब्बत की जनता, उनके धर्म, संस्कृति, परंपरा को खत्म करना असामान्य बात नहीं है और वह चाहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में तिब्बती जनता को आवाज उठाने की इजाजत न दी जाए। दमनकारी चीन का समर्थन करना लोकतांत्रिक देश नेपाल और लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मीडिया के लिए तो और भी अनुपयुक्त है जो कि एक लोकतंत्र में ही फल–फूल सकता है। इसलिए नेपाली मीडिया को इस सच्चाई को जरूर समझना चाहिए, अन्यथा दमन, अन्याय, हत्या, हिंसा, आतंक और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के उनके नैतिक अधिकार पर सवालिया निशान लग जाएगा। जो लोग अपनी मातृभूमि से विस्थापित किये गए हैं, जिनके लिए अन्याय, दमन और आतंक को सहन करना संभव नहीं रहा वे किसी भी तरह की सहानुभूति हासिल न होने पर खुद को आग लगा ले रहे है, लेकिन हम अब भी तानाशाहों का समथ.न करना चाहते हैं! हम लोकतंत्र और गणतंत्र के लिए नैतिक रूप से बात करने में सक्षम रह पाएंगे। नेपाल रिपब्लिक पार्टी चीन सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना करती है कि वह तिब्बती जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और आज़ादी को छीन रही है, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट कर रही है और तिब्बती जनता का दमन कर रही है। इसी तरह हम चाहते हैं कि दमनकारी चीन सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाली नेपाल सरकार के अलोकतांत्रिक और जनता विरोधी विच.ारों में तत्काल बदलाव लाया जाए। हम नेपाल सरकार को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि चीन की अखंडता सम्मान करना और नेपाली जमीन पर चीन विरोधी गतिविधियां न होने देने की प्रतिबद्धता का मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली तिब्बती जनता का दमन किया जाए। यदि नेपाल अपने को पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश कहलाना पसंद करता है तो उसे लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों और मानकों का सम्मान करना चाहिए और दुनिया के किसी भी हिस्से में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों के प्रति एकजुटता दिखाने से नहीं हिचकना चाहिए।

(वरिश्ठ पुलिस अधिकारी रहे और एक्टिविस्ट श्री सिद्धार्थ गौतम अब नेपाल रिपब्लिक पार्टी से जुड़े हैं) ◆

तिब्बत के पंचेन लामाः 25 साल बाद

(तिब्बत डॉट नेट, 30 जनवरी, 2014)
थुबटेन सामफेल

वर्ष 1954 में माओ, उनके बाएं दलाई लामा और उनके दाएं पंचेन लामा।

25 साल पहले 28 जनवरी को तिब्बत के दसवें पंचेन लामा का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। लोकप्रिय तिब्बती मान्यताओं के अनुसार 14वें दलाई लामा और 10वें पंचेन लामा को तिब्बती बौद्ध नक्षत्र का "सूर्य और चंद्रमा" माना जाता है। वे बौद्ध सभ्यता के केंद्र हैं जो करोड़ों गैर बौद्धों को भी आकर्षित करता है। दसवें पंचेन लामा का तिब्बती लोगों के लिए इतना महत्व है कि उनका संक्षिप्त जीवन किसी राजनीतिक ट्रेजेडी से बचा रहा और वह तिब्बत में आध्यात्मिक विजय का दौर था। लेकिन आज तिब्बती बौद्ध नेताओं को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि किस तरह से तिब्बती बौद्ध धर्म ऐसी व्यवस्था के साथ सह–अस्तित्व बनाए रख सकता है जो कि अपना पूरा प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है और किसी प्रतिस्पर्धी को बर्दाश्त नहीं करता है।

हालांकि, चीनी कम्युनिस्ट व्यवस्था के भीतर रहकर काम करने वाले पंचेन लामा उसके सबसे मुखर आलोचक हैं। उन्होंने यह कैसे किया यह एक साहस, व्यक्तिगत दुख की कहानी है और यह उनकी इस सोच को भी दिखाता है कि तिब्बत किस तरह से अपनी बौद्ध आत्मा को खोये बिना उत्पादक रूप से आधुनिक चीन के साथ सह अस्तित्व कायम रख सकता है।

वर्ष 1959 की जनक्रांति (जिससे दलाई लामा को 87,000 तिब्बतियों के साथ निर्वासित होकर भारत जाना पड़ा था) के वर्षों बाद तिब्बती पंचेन लामा के बारे में फीका नजरिया रखते हैं। इस कूच के बाद सभी प्रमुख बौद्ध धर्म गुरु भारत में बस गए। पंचेन लामा के बारे में तिब्बतियों का फीका नजिरया इसलिए है कि वह ऐसे लामा थे जो तिब्बत में 'रुके रह गए' जिसका मतलब यह निकलता था कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल गए थे। लेकिन तिब्बत के बाहर रहने वाले तिब्बतियों के लिए अनजान 24 वर्षीय पंचेन लामा ने 1962 में माओ त्से तुंग सहित शीर्ष चीनी नेताओं को अपनी 70,000 अक्षरों वाली याचिका सौंपी। यह एक ऐसा दस्तावेज था जो तिब्बत में चीनी शासन का सबसे विस्तृत और व्यापक

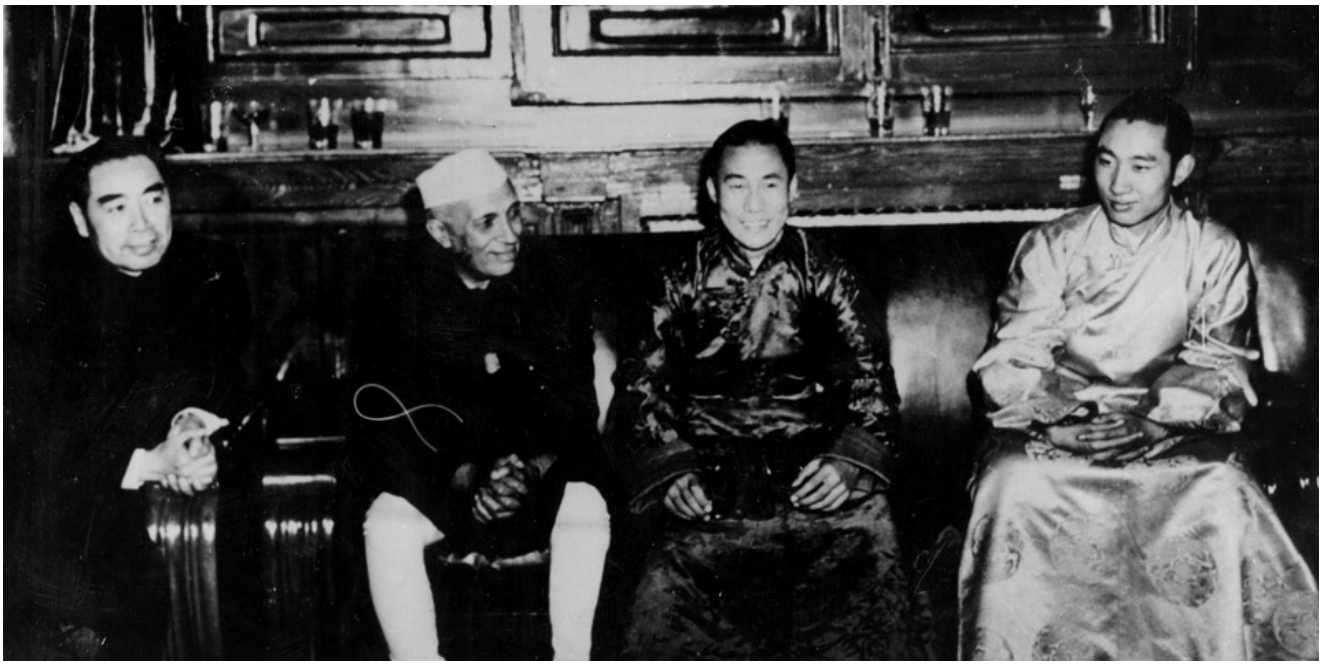

नई दिल्ली में 1957 में (बाएं से दाएं) चीन जनवादी गणराज्य के प्रधानमंत्री चाउ एन–लाई, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, परमपावन दलाई लामा और पंचेन लामा।

आलोचना थी। अपनी पुस्तक हंग्री घोस्टः चाइनाज सीक्रेट फैमिन में जास्पर बेकर लिखते हैंः "तिब्बत के दूसरे सर्वोच्च धार्मिक नेता ने एक तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर सुनियोजित नरसंहार का आरोप लगाया था।"

अपनी याचिका में, पंचेन लामा ने तिब्बत में अभूतपूर्व अकाल और भुखमरी का विवरण दिया है। सशस्त्र जनक्रांति में शामिल होने के थोड़े भी संदेह होने पर हजारों तिब्बतियों की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी और जेल में डाल देने का भी उन्होंने दस्तावेज पेश किया है। अपनी रिपोर्ट में पंचेन लामा ने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म जिसने तिब्बती संस्कृति की बुनियादी रखी, विलुप्त होने के कगार पर है क्योंकि उस मठीय शिक्षा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसने लगातार तिब्बती बौद्ध सभ्यता को ताजा और टिकाऊ रखा है। पंचेन लामा ने कहा कि चीनी भाषा के प्रभुत्व वाली शिक्षा प्रणाली में तिब्बती भाषा अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और टिकी हुई है।

माओ–त्से तुंग ने पंचेन लामा की याचिका को "एक तिब्बती सामंती कुलीन" द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर चलाया गया "विषाक्त तीर" बताया था। चीन के महान कर्णधार ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता की एक "वर्ग शत्रु" के रूप में आलोचना की थी। युवा लामा की सार्वजनिक तौर पर निंदा की गई और उन्हें लंबी अदालती प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 साल जेल में बिताए। लेकिन तिब्बती नेता के लिए मुश्किल यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। करीब 14 साल तक गायब के दौरान किसी को यह नहीं पता था कि वे कहां हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन यह संदेह तब दूर हो गया जब 26 फरवरी 1978 को चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने बीजिंग के जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन के दौरान उनकी उपस्थिति की घोषणा की। वर्ष 1980 में पंचेन लामा को चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का वाइस चेयरमैन बनाया गया। वर्षों तक सार्वजनिक अपमान और कालकोठरी की सजा भोगने के बाद भी चीन की तिब्बत नीति के बारे में उनकी तीखी राय कमजोर नहीं पड़ी थी और न ही उनकी ऊर्जा में कोई कमी आई थी। तुलनात्मक रूप से नई आज़ादी और राजनीतिक पुनर्वास के बाद पंचेन लामा फिर से मोर्चे पर लौट आए। ल्हासा में 1985 में मोनलम फेस्टिवल (महान प्रार्थना उत्सव) को संबोधित करते हुए पंचेन लामा ने कहा था, "परमपावन दलाई लामा और मैं आध्यात्मिक मित्र हैं। परमपावन दलाई लामा और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी।"

9 जनवरी, 1989 को पंचेन लामा ने शिगास्ते का दौरा किया। शिगास्ते तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पंचेन लामाओं का परंपरागत गढ़ रहा है। यहां वह अपने मुख्यमठ टाशी ल्हुनपो में पांचवें से नौंवें पंचेन लामाओं के पुनरुद्धार किये गए समाधि को जनता को समर्पित करने के लिए गए थे। इसके बाद 24 जनवरी को अपने मठ के भिक्षुओं और शिगास्ते की जनता को संबोधित करते हुए पंचेन लामा ने कहा कि तिब्बत में चीनी शासन से तिब्बती जनता के फायदा होने की जगह विनाश ज्यादा हुआ है।

अपने 70,000 अक्षरों वाली याचिका के बाद भी पंचेन लामा जिंदा बचे रहे थे, लेकिन चीनी शासन पर उनके अंतिम विचार उनके लिए जीवन गंवा देने वाला साबित हुआ। चीनी शासन की कठोर आलोचना करने के पांच दिन बाद 28 जनवरी को वह अपने मठ में मृत पाए गए। उनकी मौत के बाद दो–दो पंचेन लामा का लफड़ा देखने को मिला। एक को दलाई लामा ने मान्यता दी

वर्ष 1989 में तिब्बत में पंचेन लामा और हू जिनताओ।

तो दूसरे को बीजिंग ने नियुक्त किया। इसाबेल हिल्टन के द सर्च फॉर द पंचेन लामा में इस कहानी को दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। मई 1995 में दलाई लामा ने तिब्बत में एक छह साल के बच्चे गेदुन छोक्यी निमा की दसवें पंचेन लामा के वैध पुनर्जन्म के रूप में पहचान की। चीन इस बच्चे और उसके परिवार को बीजिंग उठा ले गया। इसके बाद से कोई यह नहीं जानता कि तिब्बत के असल पंचेन लामा कहां हैं, उनका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है या वह किस तरह की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उसी साल नवंबर में बीजिंग ने छह साल के एक और बच्चे ग्यालत्सेन नोर्बू को अपनी तरफ से पंचेन लामा घोषित किया। वह भी बीजिंग में रहते हैं क्योंकि उनके मठ टाशी ल्हुनपो के भिक्षु बीजिंग के चुने हुए इस लामा से इतने खफा थे कि उन्हें अपने मठ परिसर में रहने या अध्ययन की इजाजत नहीं दे रहे थे। अपने पंचेन लामा को पालने–पोसने के पीछे चीन की सोच एक बड़ी सफलता हासिल करने की तरफ थीः 15वें दलाई लामा की पहचान का काम अपने नियंत्रण में लेना। अब ग्यलात्सेन नोर्बू खुद अपने आध्यात्मिक वजन का इस्तेमाल इस तरह करने देने के लिए प्यादा बन जाते हैं या नहीं, यह आने वाले वर्षों में उनके चरित्र और अपनी आध्यात्कि विरासत के प्रति वफादारी का परीक्षण साबित होगा।

हालांकि, दसवें पंचेन लामा की सबसे महान विरासत उनके द्वारा करिश्माई बौद्ध नेता खेनपो जिग्मे फुंत्सोक को दी गई वह सलाह हो सकती है, जो देंग के चीन में तुलनात्मक रूप से थोड़ी आज़ादी और उदारीकरण के बीच तिब्बती बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करना चाहते थे। वह तिब्बत में एक मठ की स्थापना करना चाहते थे जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म के सभी चार मतों की आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जा सके। पंचेन लामा ने खेनपो जिग्मे फुंसोक को उनके इस प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन पंचेन लामा ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नए मठों पर प्रतिबंध के माहौल को देखते हुए प्रशासन को धोखा देने के लिए उन्हें अपने स्कूल का नाम कोई "आश्रम" रखना चाहिए। खेनपो जिग्मे फुंत्सो ने 1980 में सिचुआन प्रांत के कार्डजे में तिब्बत बहुल इलाके लारुंग घाटी में सरथार बौद्ध अकादमी की स्थापना की। जल्दी ही इस अकादमी में न सिर्फ समूचे तिब्बत से बल्कि ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और मुख्य चीन से भी विद्यार्थी आने लगे। वर्ष 2001 तक जब चेंगदू के घबराए प्रांतीय अधिकारियों ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आवास को ढहा दिया और सभी बाहरी लोगों को बाहर कर दिया तब इस अकादमी में 10,000 विद्यार्थी थे जिसमें से करीब 1000 विद्यार्थी मुख्य भूमि चीन से थे।

सरथार बौद्ध अकादमी इस विनाश अभियान से बचा रहा। अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या और भी बढ़ गई है और इसमें बड़ी संख्या चीनी विद्यार्थियों की है। यह शायद स्वर्गीय पंचेन लामा की विरासत है और आध्यात्मिक तिब्बत की भौतिकवादी चीन के ऊपर विजय भी।

(थुबतेन सामफेल तिब्बत नीति संस्थान के निदेषक हैं जो भारत के धर्मषाला षहर में स्थित एक अनुसंधान केंद्र है) ◆

एषिया में जल षाप

(ब्रह्मा चेलानी, वर्ल्ड पॉलिसी)

कम्बोडिया का एक श्रमिक मेकांग नदी के किनारे बालू ढोते हुए। नदी के निचले जल स्तर से प्रभावित किसान और मछुआरे चीन के प्रति गुस्से का इजहार करते हुए। फोटोः तांग छिन सोथी/एएफपी–गेट्टी इमेजेज

एशिया एक उभयसंकट का सामना कर रहा है। इस महाद्वीप में सबसे कम वैश्विक प्रति व्यक्ति ताजा जल संसाधन है, वैश्विक सालाना औसत 2,22,480 क्यूबिक फीट प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम। दूसरी तरफ, एशिया में पानी की मांग सबसे तेजी से बढ़ रही है। एशिया ने यदि अपने जल संकट का समाधान नहीं किया तो उसका वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अगुआ बने रहना मुश्किल है।

एशिया के लगातार बढ़ते जल की तंगी में, जल के लिए जारी संघर्ष राजनीतिक तनाव को भी बढ़ावा दे रहा है। इससे पारिस्थतिकी तंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में जल की स्थिति बिगड़ती जा रही है और कम विकसित देशों में भी यही हाल है जहां जनसंख्या वृद्धि दर काफी ज्यादा है। कई एशियाई देशों में नए मैन्युफैक्चरिंग या ऊर्जा कारखाने लगाने का निर्णय लगातार सीमित होता जा रहा है क्योंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि चीनी में जल की तंगी का उसके जीडीपी पर 2.3 फीसदी तक असर पड़ रहा है। हालांकि, चीन को अभी "वाटर स्ट्रेस" (जल की तंगी) वाला देश नहीं माना जाता, यह एक ऐसा शब्द है जो उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 60,000 क्यूबिक फीट जल उपलब्ध है, लेकिन पहले से ही जल तंगी वाले देश जैसे दक्षिण कोरिया, भारत आदि को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

इस तरह की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के प्रतिस्पर्धी देश जल युद्ध के मुहाने पर हैं। बांध या अंतरराष्ट्रीय नदी बनाने की युक्ति अपनाई जा रही है, इसलिए यदि कोई देश निचली जलधारा पर स्थित है तो उसे ऐसे निर्माण को रोकने का प्रतिरोधी कदम उठाना पड़ रहा है। चीन–भारत संबंधों के मामले में जल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा मसला बन गया है और गंभीर अनबन का संभावित स्रोत भी। कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय नदियों के शुरुआती उदगम स्थल का ही गला घोंट कर चीन पनबिजली में अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है और अब वह तिब्बती पठार में लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षा वाले बांध निर्माण कार्यक्रम चला रहा है जिससे अंतरराष्ट्रीय नदियों का भारत और अन्य देशों में प्रवाह सीमित हो जाता है जो इन जल संसाधनों को साझा करते हैं।

जल युद्धों को टालने के लिए नियम आधारित सहयोग, जल साझेदारी और विवाद निपटान तंत्र कायम करने की जरूरत है। हालांकि, चीन ऊपरी ६ाराओं पर व्यापक रूप से पनबिजली

परियोजनाओं का निर्माण करके एशिया के जल संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। चीन ने अपने किसी भी पड़ोसी देश से एक भी जल साझेदारी समझौता नहीं किया है।

इसके विपरीत, भारत ने अपनी दो निचली जलधाराओं वाले पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जल संधि किया है जिसके तहत सिंधु और गंगा नदी शामिल हैं और भारत अंतरराष्ट्रीय जल कानून में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। वर्ष 1996 में गंगा समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को यह गारंटी दी है कि कठिनाई वाले सूखे के मौसम में भी निचली जलधाराओं की बराबर की साझेदारी की जाएगी। वर्ष 1960 का सिंधु समझौता दुनिया का सबसे उदार जल साझेदारी समझौता कहा जा सकता है। इस समझौते के तहत भारत ने सिंधु प्रणाली की छह नदियों का 80 फीस. दी जल पाकिस्तान को अनिश्चिकाल तक छोड़ते रहने का वादा किया है, इस उम्मीद में कि वह इस जल आपूर्ति के बदले शांति हासिल कर सकता है। एशिया के लिए आज केंद्रीय मसला यही है कि चीनी नेताओं को इस बात के लिए किस तरह से राजी करें कि वह पड़ोसी देशों के साथ संसाधनों के साझेदारी के लिए सहयोग करे। एशिया के जल नक्शे पर चीन की केंद्रीयता को देखते हुए विशाल बांध बनाने की उसकी हवस से पूरे एशिया में रिश्ते खराब हो रहे हैं और किसी भी नियम आध ाारित एशियाई जल व्यवस्था पर जोखिम बना हुआ है।

(ब्रह्मा चेलानी वाटर, पीस ऐंड वारः कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस के लेखक हैं, इसके पहले आने वाली उनकी पुस्तक वाटरः एषियाज न्यू बैटलग्राउंड को वर्ष 2012 का बर्नार्ड ब्रॉवर्ड्ज अवॉर्ड भी मिल चुका है) ◆

षी तिब्बत की समस्या का हल किस तरह से निकाल सकते हैं

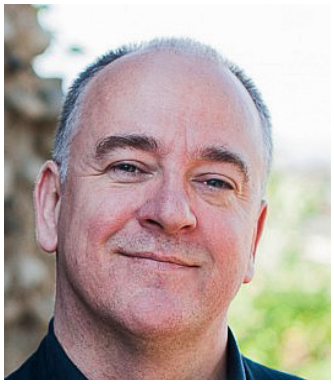

(तिब्बत डॉट नेट, 20 जनवरी, 2014)
केरी ब्राउन

शी जिनपिंग तिब्बत में अशांति को कम करने में मदद कर सकते हैं, बस यह सुनिश्चित करके कि मौजूदा नीतियों को ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाए

हर राजनीतिक संस्कृति में–यहां तक कि उसमें भी जहां निरंतरता, आमराय और एकता पर जोर दिया जाता है–कई बिंदुओं पर चुने हुए नेता अपने अहं को तुष्ट करने के मुताबिक प्रतिक्रिया देते हैं। नेता आखिरकार यह चाहते हैं कि उनकी अपनी नीतियों को बढ़ावा दिया जाए, बजाय उनके पूर्ववर्तियों से विरासत में मिली नीतियों के। ब्रिटेन में एक स्थानीय सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते हुए मैंने एक स्थानीय नेता से एक इलाके के नेता के बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि वह नेता अपने एक पूव. र्वर्ती के "भोंपू" जैसे ही हैं, जो कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पद तो छोड़ चुके हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से अब भी सक्रिय बने हुए हैं। इस पर उस नेता ने मुझसे कहा, "मुझे लगता है कि आपको यह देखने को मिलेगा कि सत्ता में आने के बाद जो लोग इस तरह से कार्य शुरू करते हैं, वे जल्दी ही अपने दम पर काम करने की इच्छा रखते हैं।" इस अर्थ में मानव स्वभाव वास्तव में सार्वभौमिक है।

वर्ष 2012 के अंत में शुरू होने वाले चीनी नेतृत्व परिवर्तन के समय नीतियों को जारी रखने की बात भी कही गई थी। शी जिनपिंग और ली केक्यांग ऐसा नहीं चा. हते होंगे कि अपने कार्यकाल के पहले ही हफ्ते में हू जिनताओ और वेन जियाबाओ के नीतिगत ढांचे को बिखेर दें। लेकिन, अब साफ और साफ तौर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उनमें नीतिगत अंतर है, चाहे विदेशी नीति का मसला हो, पार्टी अपने मुख्य संदेश को किस तरह से प्रेषित करती है या सामाजिक न्याय एवं नौकरशाही की जिम्मेदारी तय करने पर जो जोर दिया है। इन महत्वपूर्ण बदलावों में सबसे ज्यादा नाटकीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है। इसके बावजूद, शी और ली के नेतृत्व की असली परीक्षा इस बात से होगी कि क्या वे सबसे मजबूत नीतिगत ढांचे को चुनौती दे पाते हैं, या इसमें विफल रहते हैं। तिब्बत के मसले को किस तरह से हल किया जाता है, इससे ज्यादा दिलचस्प बात देखने लायक कोई और नहीं होगी। तिब्बत में दुःखद रूप से आत्मदाह जारी हैं, यह इस बात का संकेत है कि असंतोष कम नहीं हुआ है। पार्टी के नए सचिव ने पहले अपने पूर्ववर्ती नेता के प्रति ज्यादा लचीलापन दिखाया था, लेकिन स्वायत्त क्षेत्र के प्रबंधन के बारे में वर्ष 2010 की केंद्रीय बैठक में जो पैरामीटर तय किये गए थे वह अभी तक लागू हैं। तिब्बत के लिए मौजूदा रणनीति यह है कि आर्थिक विकास को सहयोग दिया जाए इससे ही इलाके में दूसरे सभी मसलों का उपचार हो जाएगा।

शी के हाल के कार्य ऐसा लगता है कि वे विकेंद्रीकरण के तर्क को अपना रहे हैं, जिसके तहत प्रांतों को ज्यादा वित्तीय अधिकार दिये जाएंगे, जबकि प्रांतीय नेतृत्व के प्रति एक ज्यादा वफादार, साफ–सुथरा और भरोसेमंद काडर तैयार किया जाएगा। कुछ इसी तरह का विचार नवंबर 2013 के दौरान हुए तीसरे प्लेनम के दौरान भी आगे बढाया गया था। इस रणनीति से स्वायत्तशासी क्षेत्रों में (तिब्बत और शीक्यांग इनमें से सबसे चुनौतीपूर्ण हैं) पनपे भारी असंतोष को कुछ हद दूर करने का मौका मिल सकता था, जिसके लिए ज्यादा स्थानीय नेतृत्व को उभारना होता और सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ता। इसके लिए ढांचा तैयार था और इसके लिए बौद्धिक तर्कसंगतता भी मजबूत थी। प्रभावी प्रशासन निश्चित रूप से स्थानीय अधिकारियों को ज्यादा वित्तीय अधिकार देने की मांग करता है और इस बात की भी कि ज्यादा निर्णय उन इलाकों के आसपास ही लिए जाएं जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं। पर्याप्त रूप से सरकारी उद्यमों की स्थापना की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारी उद्यम (एसओई) तिब्बती अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और राष्ट्रीय सुधार प्रयास निश्चित रूप से इस बात को प्रभावित करते हैं कि ये कंपनियां तिब्बत में किस तरह से संचालित होती हैं।

बोल्डर यूनिवर्सिटी के एमिली येह द्वारा तिब्बती अर्थव्यवस्था के बारे में किये गये एक बेहतरीन नए अध्ययन इन टैमिंग तिब्बत में येह उन बुनियादी चुनौतियों के बारे में बताते हैं जो नए विकेंद्रीकरण की नई संभावना का इस्तेमाल करते

हुए इलाके को "सामान्य" बनाने में सामने आ सकती हैं। उनके गहन और सतर्क फील्ड रिसर्च से यह पता चलता है कि केंद्रीय सरकार ने इस इलाके में जो सब्सिडी दी है, जो तिब्बत के राजस्व का करीब 80 फीसदी हिस्सा है, वह काफी हद तक तिब्बत में बाहर से काम के लिए आने वाले लोगों की जेब में चला जाता है। ये श्रमिक, जिनमें से ज्यादातर सिचुआन प्रांत के हैं, काफी धन अपने मूल इलाके में भेज देते हैं। निर्माण मजदूर और सर्विस सेक्टर के कामगार, पूरे चीन में दिखने वाले प्रवासी श्रमिक, तिब्बत में भी अक्सर सीजन के मुताबिक मौजूद रहते हैं। ये श्रमिक केंद्र सरकार के अनुदान और प्रोजेक्ट से मिलने वाले धन के मुख्य हासिलकर्ता होते हैं, जबकि यह किसी योजना के तहत नहीं बल्कि दुर्घटनावश हो रहा है।

इस तरह के पूंजी के पुनर्चक्रण के बावजूद केंद्रीय नीति–नियंता इसे कोई जटिल राजनीतिक या नस्लीय मसला नहीं मानते बल्कि ज्यादा कारगर तरीका मानते हैं: किस तरह से ऐसे इलाके में ज्यादा प्रभावी तरीके से पूंजी लगाई जाए जहां निवेश अंततः कहीं और जाकर खत्म होता हो। येह के अध्ययन के मुताबिक तो तिब्बत में जीडीपी ग्रोथ दिखावटी ही है क्योंकि इससे काफी हद तक उन लोगों को फायदा मिलता है, जो इस इलाके के नहीं हैं। यह केंद्र सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। साफ कहें तो फिलहाल तो बीजिंग जो सब्सिडी दे रहा है, वह इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि उससे इलाके में दीर्घकालिक टिकाऊ वृद्धि लाने का लक्ष्य पूरा नहीं होता।

क्या केंद्रीय नेतृत्व के पास इस तरह के मसलों को हल करने और मौजूदा समय के मुकाबले ज्यादा उन्नत नीतियां बनाने के लिए राजनीतिक परिकल्पना है? एक बेहतर राजकोषीय व्यवस्था यह सुनिश्चित कर सकती है कि आर्थिक गतिविधियों का फायदा उन लोगों को मिले जो सबसे मजबूत तरीके से अपने असंतोष को पूरा कर रहे हैं। यह इलाके में केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करने वालों को एक ताकतवर जवाब भी हो सकता है। इस समय तो सीधा तथ्य यही है कि सरकार की मौजूदा नीतियां कारगर नहीं हैं और उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार के पास इसके लिए संसाधन है और उसमें इतनी क्षमता है कि इस इलाके में कुछ ताजी सोच लेकर आए। आखिरकार, वित्तीय ढांचे और आर्थिक निर्णय लेने की सक्षमता के लिहाज से देखें तो तिब्बत का मसला जातीय संघर्ष और राजनीतिक असंतोष की परंपरागत समस्या नहीं है। इसकी जगह समस्या सामाजिक न्याय और नीतिगत स्थिरता से जुड़ी है–बिल्कुल वही क्षेत्र जहां शी और ली का नेतृत्व काम करना चाहता है। ◆

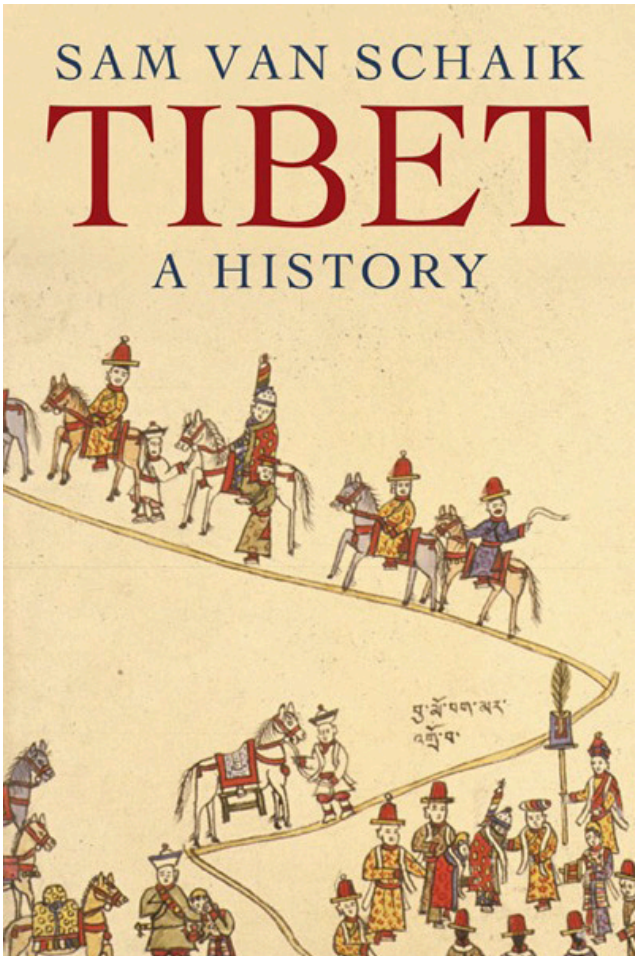

तिब्बतः अ हिस्ट्री

लेखकः सैम वैन षाइक

प्रकाषकः येल यूनिवर्सिटी प्रेस

समीक्षकः टॉम ल्यूहौस (डर्बी यूनिवर्सिटी)

कीमतः 25 पाउंड

जब ज्यादातर पाठक तिब्बत के बारे में सोचते हैं तो वे शांतिप्रिय तिब्बती बौद्धों के बारे में, दलाई लामा के बारे में और चीनी दमन के बारे में सोचते हैं। इस संबंध में पश्चिमी दुनिया ने अक्सर तथाकथित "दुनिया की छत" के बारे में कई तरह के मिथक और परिकल्पनाएं गढ़ रखी हैं। इसी तरह, तिब्बती इतिहास चीन के भीतर तिब्बत के दर्जे के बारे में बहस के लिए राजनीतिक औजार बन गया है क्योंकि चीनी इतिहासकार इसमें पिछली शताब्दियों में तिब्बत की चीन पर निर्भरता के बारे में प्रमाण तलाशते हैं।

तिब्बतः अ हिस्ट्री में सैम वैन शाइक सातवीं सदी से मौजूदा समय तक तिब्बत के इतिहास पर एक नजर डालते हैं और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं जो बहुत तरह की पूर्व धारणाएं पाठकों के मन में तिब्बत, उसके धर्म, समाज और राजनीति के बारे में बनी होती हैं। तिब्बती इतिहास का दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैन शाइक की किताब में सबसे प्रमुख तरीके से सामने आता हैः तिब्बती बौद्ध धर्म का पारदर्शी प्रकार और यह तथ्य कि तिब्बत का बाहरी ताकतों से लगातार संवाद होता रहा है।

सातवीं सदी से ही सांगतसेन गाम्पो और उनके उत्तराधिकारियों के शासन में तिब्बती साम्राज्य काफी आगे बढ़ा और एक समय तो उसने चीनियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण भी किया। इसके बाद की शताब्दियों में धीरे–धीरे बौद्ध धर्म के विभिन्न मतों का तिब्बत में आगमन होता है, जिनकी पूजा पद्धति में काफी विविधता है। धार्मिक विविधता तिब्बती साम्राज्य के पतन के बाद भी काफी आगे बढ़ी और विभिन्न तरह के धर्मगुरुओं ने स्थानीय और बाहरी शासकों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाई। सोलहवीं सदी से गेलुप्पा मत और दलाई लामा की जुड़ी हस्ती का तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के रूप में उभार शुरू हुआ; यह काफी हद तक उनके मंगोलों और बाद में चीन के नए मांचू वंश के शासकों के साथ बेहतर संबंधों की वजह से था। चीनी साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया, लेकिन ब्रिटेन और रूस के बीच प्रतिस्पर्धा की वजह से सत्ता के नए समीकरण बनने लगे। बाद में राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट चीन से खतरा बढ़ने लगा। कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर हमला और उसे 1950 के दशक में चीन जनवादी गणराज्य में मिला लेने से तिब्बतियों की पहचान, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में उनका स्थान और तिब्बती बौद्ध धर्म की नियति के बारे में कई तरह के सवाल खड़े हुए जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं।

इस किताब के कई खंड अकादमिक अर्थों में मूल बिंदुओं को उठाते हैं, लेकिन इसमें आम पाठकों के लिए भी काफी कुछ है। पूरे पुस्तक को पढ़ने के दौरान पाठकों को यह लगेगा कि तिब्बत के बारे में विचार को लगातार चुनौती दी जा रही है।

हमें तिब्बती एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखते हैं जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे जिसका क्षेत्र मौजूदा चीन और मंगोलिया तक फैला हुआ था। हमें यह पता चलता है कि केवल पांचवें और 13वें दलाई लामा ने वास्तव में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हमें इन शताब्दियों के दौरान बौद्ध धर्म के उपदेशों में हुए तमाम संशोधनों के बारे में पता चलता है, जिससे साफ तौर से यह दिखता है कि मौजूदा तिब्बती बौद्ध धर्म अन्य धर्मों की तरह ऐतिहासिक रूप से निर्मित हुआ है। वैन शाइक ऐतिहासिक चरित्रों को जिस गहनता से पेश करते हैं वह कई बार सामान्य पाठक को हक्का–बक्का कर देता है। 'सामान्य तिब्बतियों' के जीवन के बारे में यदि और सामग्री होती, हालांकि यह कठिन है, तो यह पुस्तक और रोचक हो जाती। साथ ही, तिब्बती कहानियों और किवदंतियों के बारे में बताने के लिए इस पुस्तक में जिस तरह बड़े पैमाने पर तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है वह उन पाठकों के लिए थोड़ा अनोखा हो सकता है जो पश्चिमी तर्ज पर इतिहास पढ़ते आए हैं।

फिर भी, ये कहानियां और किवदंतियां ही वास्तव में एक व्यापक पाठक वर्ग के लिए इस पुस्तक को मनोरंजक बनाती हैं। ◆